Page Three

Classified

Adds can be booked under these Categories : (all day publication)

Recruitment
Property
Business Opportunity
Vehicles
Announcements
Antiques & Collectables
Barter
Books
Computers
Domain Names
Education
Miscellaneous
Entertainment & Event
Hobbies & Interests
Services
Jewellery & Watches
Music
Obituary
Pets & Animals
Retail
Sales & Bargains
Health & Sports
Travel

Matrimonial (Sunday Only)

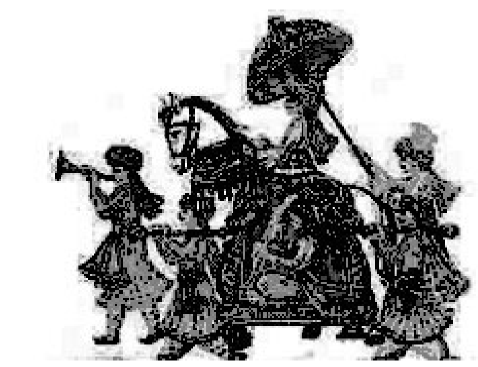

अब मात्र रू. 20 प्रति शब्द

15वें वित्त आयोग ने की उत्तराखण्ड को राजस्व घाटा अनुदान की संस्तुति

संस्तुति

राजस्व घाटा अनुदान से उत्तराखण्ड को प्रतिवर्ष 2 हजार करोड़ रूपए से अधिक का लाभ होगा

संवाददाता

देहरादून। मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत की 15 वें वित्त आयोग के समक्ष राज्य के हक में की गई पैरवी आयोग की सिफारिशों में देखने को मिल रही हैं। 15वें वित्त आयोग द्वारा उत्तराखण्ड राज्य को राजस्व घाटा अनुदान दिये जाने की संस्तुति की गई है, जिसके फलस्वरूप राज्य को प्रतिवर्ष लगभग न्यूनतम रू 2000 करोड़ का लाभ होगा। आयोग की सिफारिशों में केन्द्रीय करों में राज्य का अंश 1.052 से बढ़ाकर 1.104 कर दिया गया है, जिससे राज्य को प्रतिवर्ष लगभग रू. 300 से 400 करोड़ का लाभ होगा। डिवोलेशन फार्मूला में वनों का अंश 7.50 प्रतिशत से बढ़ाकर 10 प्रतिशत कर दिया गया है, जिसे राज्य के अंश में वृद्धि हुई है।

राज्य आपदा राहत निधि के अंश में 787 करोड़ रूपए वृद्धि पर सहमति दी गई है। शहरी स्थानीय निकायों एवं पंचायतीराज संस्थाओं के अनुदान में भी 148 करोड़ रूपए की वृद्धि हुई है। 15 वें वित आयोग की सिफारिशों पर मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा कि, 15वें वित्त आयोग के समक्ष राज्य के पक्ष को तार्किक ढंग से बहुत ही स्पष्ट एवं सक्षम तरीके से प्रस्तुत किया गया। उसी का परिणाम है कि विभिन्न बिंदुओं पर आयोग ने अपनी सहमति देते हुए राज्य के पक्ष में संस्तुतियां की हैं। उत्तराखण्ड के दृष्टिकोण को समझने और तद्नुसार संस्तुतियां देने के लिए 15 वें वित आयोग का आभार व्यक्त करते हैं। इससे उत्तराखण्ड विकास के पथ पर और तेजी से आगे बढ़ेगा।

15 वें वित्त आयोग को संदर्भित विषयों एवं राज्य की विभिन्न समस्याओं के संबंध में मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत के नेतृत्व में मैमोरेण्डम प्रस्तुत किया गया था। उत्तराखण्ड द्वारा मैमोरेण्डम में विभिन्न बिन्दुओं को स्पष्ट एवं विश्वसनीय तरीके से प्रस्तुत किया गया, जिसे आयोग द्वारा स्वीकार किया गया। उत्तराखण्ड राज्य के परिदृश्य में आयोग द्वारा स्वीकार किया गया है कि राज्य द्वारा पूरे देश को बहुमूल्य ईको–सिस्टम सेवायें प्रदान की जा रही हैं। इसके लिये 15 वें वित्त आयोग से डिवोलेशन फार्मूला में वनों का अंश बढ़ाये जाने का अनुरोध किया गया था, जिसे ग्रीन बोनस भी कह सकते हैं। 15वें वित्त आयोग द्वारा डिवोलेशन फार्मूला में वनों का अंश 7.50 प्रतिशत से बढ़ाकर 10 प्रतिशत कर दिया गया है, जिससे राज्य के अंश में वृद्धि हुई है।

मुख्यमंत्री ने सांवैधानिक व्यवस्था के अनुरूप 15 वें वित्त आयोग के समक्ष राज्य के हक की पुरजोर पैरवी करते हुये कहा था कि 14वें वित्त आयोग द्वारा राजस्व घाटा अनुदान को समाप्त कर दिया था, जिसके कारण राज्य को अत्यधिक नुकसान उठाना पड़ा। 15वें वित्त आयोग ने इस बात को स्वीकार करते हुए उत्तराखण्ड राज्य को राजस्व घाटा अनुदान दिये जाने की संस्तुति की है, जिसके फलस्वरूप राज्य को प्रतिवर्ष लगभग न्यूनतम रू 2000 करोड़ का लाभ होगा। आपदा प्रबन्धन के अन्तर्गत राज्य को राज्य ''आपदा राहत निधि'' के अंश के रूप में गतवर्ष लगभग रू. 254 करोड़ की धनराशि प्राप्त होती थी।

कर–अंतरण फार्मुला में वनों का अंश 10 प्रतिशत करने से उत्तराखण्ड को मिलेगा फायदा

उत्तराखण्ड राज्य में होने वाली प्राकृतिक आपदाओं से निटने के लिये आवश्यक सहायता दिये जाने का विषय आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया गया। राज्य से सहमत होते हुये 15वें वित्त आयोग द्वारा राज्य आपदा राहत निधि के अंश में वृद्धि करते हुये, इसे प्रतिवर्ष लगभग रू 1041 करोड़ कर दिया गया है। 14वें वित्त आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2019–20 में मूल अनुदान के अन्तर्गत शहरी स्थानीय निकायों एवं पंचायतीराज संस्थाओं हेतु कुल रू 704.10 करोड़ की धनराशि संस्तुति की गई थी। 15वें वित्त आयोग द्वारा शहरी स्थानीय निकायों एवं पंचायतीराज संस्थाओं हेतु अनुदान में वृद्धि करते हुये वित्तीय वर्ष 2020–21 हेतु कुल रू 852.00 करोड़ की धनराशि संस्तुत की गई है, जिसमें लगभग 21 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

न्यूज डायरी

चुनाव प्रचार के लिए प्रीतम सिंह ने वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं को पर्यवेक्षक की जिम्मेदारी सौंपी

संवाददाता देहरादून। दिल्ली में हो रहे विधानसभा चुनावों के मद्देनजर कांग्रेस पार्टी के अधिकृत प्रत्याशियों की चुनाव प्रचार–प्रसार में सहायता हेतु उत्तराखण्ड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष प्रीतम सिंह द्वारा वरिष्ठ कांग्रेसजनों को पर्यवेक्षक की जिम्मेदारी सौंपी गई है। जानकारी देते हुए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री संगठन विजय सारस्वत ने बताया कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम सिंह द्वारा वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में पर्यवेक्षक बनाया है। उन्होंने यह भी बताया कि स्वयं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम सिंह एवं नेता प्रतिपक्ष इन्दिरा हृदयेश सहित सभी विधायकगण विधानसभा चुनावों में पार्टी के अधिकृत प्रत्याशियों की चुनाव प्रचार में सहायता हेतु दिल्ली के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों का दौरा करेंगे।

हेतु स्मार्ट सिटी एवं इन्डस टावर्स के मध्य हुई साझेदारी

संवाददाता देहरादून। देहरादून शहर के टेलीकॉम की आधारभूत संरचना को मजबूत बनाने के उद्देश्य से देहरादून स्मार्ट सिटी लिमिटेड एवं इन्डस टावर्स, जो कि विश्व की बड़ी टावर्स कंपनियों में से एक है, के साथ साझोदारी की गयी। इस परियोजना के अन्तर्गत 70 स्थानों पर जी.बी.एम टावर एवं वाई–फाई, स्मार्ट लाईटिंग एवं सी.सी.टी.वी. कैमरों युक्त 60 स्मार्ट पोलों की स्थापना की जायेगी। इसके अतिरिक्त 100 कि.मी. लम्बी भूमिगत फाईबर का नेटवर्क भी विकसित किया जायेगा। यह देहरादून स्मार्ट सिटी की द्वारा देहरादून को स्मार्ट एवं शहरवासियों को सुविधायुक्त बनाने की दिशा में लिए जा रहे बहुत से कार्यक्रमों में से एक है।

डीएम ने दो घंटे पैदल भ्रमण कर सुनीं समस्याएं, विभिन्न संस्थानों का किया निरीक्षण

संवाददाता नैनीताल। जिलाधिकारी सविन बंसल ने तयशुदा कार्यक्रम के तहत सोमवार को तल्लीताल से मल्लीताल, बीडी पाण्डे हॉस्पिटल, चीना बाबा मन्दिर, मेट्रोपोल बोट हाउस क्लब, कैपिटल सिनेमा क्षेत्र का लगभग 2 घण्टे गहनता से पैदल भ्रमण किया। उन्होंने भ्रमण के दौरान नगर सौन्दर्यकरण हेतु क्षतिग्रस्त सड़कों, म्यूरल्स स्थापना हेतु स्थानों के चिन्हीकरण, नगर पालिका लाइब्रेरी, नालों एवं शौचालयों की सफाई के साथ ही झील का भी मौका मुआयना किया। जिला प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराई गई नावों से झील की सफाई का कार्य सही से किया जा रहा है। निरीक्षण के दौरान नगर पालिका अध्यक्ष सचिन नेगी, समाज सेवी राजीव लोचन शाह मौजूद थे। उन्होंने सिंचाई विभाग के अधिकारियों कार्य शैली पर भी नाराजगी जाहिर करते हुए अधीक्षण अभियंता सिचांई को कार्यालय में तलब किया।

उत्तराखण्ड पुलिस की कार्यप्रणाली से रूबरू होने आए कर्नाटक पुलिस के दल से डीजीपी ने की भेंट

मुलाकात

देहरदून। **संवाददाता**

कर्नाटक पुलिस का दल डीजीपी उत्तराखंड के साथ।

एक भारत, श्रेष्ठ भारत की पहल के तहत उत्तराखण्ड आए कर्नाटक पुलिस के दल से आज श्री अनिल के0 रतूड़ी, पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड ने पुलिस मुख्यालय स्थित सभागार में भेंट कर दल का परिचय प्राप्त किया। कर्नाटक पुलिस का दल उत्तराखण्ड पुलिस की कार्यप्रणाली से रूबरू होने के लिए 25 जनवरी को देहरादून पहुंच था। यह दल 9 फरवरी तक देहरादून और हरिद्वार में प्रदेश की पुलिसिंग, अपराधों के ट्रेंड के अलावा विवेचनाओं और शिकायतों के निस्तारण पर अध्ययन करेगा।

अशोक कुमार, महानिदेशक, अपराध एवं कानून व्यवस्था, उत्तराखण्ड ने बताया कि गृह मंत्रालय, भारत सरकार ने देश की भाषा, सांस्कृतिक, धार्मिक विविधता में एकता बनाने के उद्देश्य से एक भारत और श्रेष्ठ भारत की पहल शुरू की गई है। जिसके अन्तर्गत एक राज्य की पुलिस दूसरे राज्यों में जाकर वहां की पुलिसिंग का अध्ययन करेंगी।

इससे एक दूसरे का भाषा समझने में मदद मिलेगी और अपराधों के ट्रेंड के अलावा विवेचनाओं और शिकायतों के निस्तारण में भी ज्ञान मिलेगा। इसी कड़ी में कर्नाटक पुलिस का 15 सदस्यीय दल उत्तराखंड पुलिस की कार्यप्रणाली देखने यहां आया है।

रेडक्रास सोसाइटी ने जरूरतमंदों को कम्बल वितरित किए

संवाददाता अल्मोड़ा। भारतीय रेडक्रास सोसायटी की जनपद शाखा द्वारा आज कलैक्ट्रेट परिसर में जरूरतमंदों हेतु आयोजित एक कार्यक्रम में कम्बल वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान अध्यक्ष रेडक्रास शाखा/जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया व रेडक्रास के अन्य पदाधिकारियों द्वारा जरूरतमंद 100 लोगो को कम्बल वितरित किये गये। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने कहा कि रेडक्रास द्वारा निस्वार्थ भावना से जरूरतमंदों को अनेक सुविधायें दी जाती है। उन्होंने कहा कि रेडक्रास द्वारा समय–समय पर विभिन्न अवसरो पर जरूरतमंदों को आवश्यकतानुसार अन्य वस्तुयें व रक्तदान शिविर, आपदा के दौरान खोज–बचाव आदि कार्यों में सहयोग किया जाता है। उन्होंने कहा कि शहर के अन्य जरूरतमंद व्यक्तियों को भी कम्बल आदि वितरित किये जायेंगे।

इस अवसर पर प्रभारी मुख्य चिकित्साधिकारी डा. योगेश पुरोहित, रेडक्रास मैनेजमेंट कमेटी के अध्यक्ष किशन गुरूरानी, राज्य प्रतिनिधि बीएस मनकोटी, समिति के सदस्य मोती लाल वर्मा, मनोज सनवाल, गिरीश मल्होत्रा, जीसी दुर्गापाल, भाजपा जिलाध्यक्ष रवि, नगर व्यापार मण्डल के अध्यक्ष सुशील शाह, मनोज, विनीत के अलावा जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे।

डीएम भदौरिया ने किया 'नेकी की दीवार' का शुभारम्भ

संवाददाता अल्मोड़ा। जिला प्रशासन व क्लब महिन्द्रा बिनसर के संयुक्त प्रयासो से कलैक्ट्रेट परिसर में ''नेकी की दीवार'' का शुभारम्भ जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया ने किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि जरूरतमंद लोगो को कपड़े, बर्तन आदि इसके माध्यम से उपलब्ध कराये जायेंगे। उन्होंने कहा कि नेकी की दीवार में क्लब महिन्द्रा का सहयोग रहा है। जिलाधिकारी ने नगरवासियों से अपील की है कि वे अपने पुराने कपड़े नेकी की दीवार में रख सकते है जिससे जरूरतमंद लोग अपनी जरूरत के हिसाब से कपड़े ले लें। उन्होंने बताया कि जिला स्तरीय अधिकारियों द्वारा नेकी की दीवार हेतु कपड़े दिये गये है। उन्होंने बताया कि यहा पर बर्तन आदि भी रखे जायेंगे जिससे किसी व्यक्ति को बर्तनों की जरूरत हो तो यहा से आकर ले सकते है। जिलाधिकारी ने कहा कि जरूरतमंद लोग कलैक्ट्रेट परिसर स्थित नेकी की दीवार से कपड़े आदि प्राप्त कर सकते है। इसके लिए जरूरतमंद लोगो से इसका लाभ उठाने की भी अपील की है।

उत्तराखण्ड पर्यटन के साथ 60 निजी होटलियर्स प्रतिभाग कर रहे मुम्बई ओटीएम में

संवाददाता

आउटबॉन्ड ट्रैलव मार्ट (ओटीएम) के उद्घाटन अवसर पर पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज।

देहरादून। मुम्बई में आयोजित आउटबॉन्ड ट्रैलव मार्ट का उद्घाटन पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज तथा ग्रीस के पर्यटन मंत्री हैरी थियोचैरिस द्वारा सयुंक्त रूप से किया गया। इस आयोजन में उत्तराखण्ड पर्यटन के साथ 60 निजी होटलियर्स द्वारा भी प्रतिभाग किया जा रहा है, जहां वे राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय होटल व्यवसाइयों से व्यवसायिक आदान प्रदान करेंगे। पर्यटन विभाग द्वारा ओ0टी0एम0 मुम्बई में औली में आयोजित नेशनल स्कीईंग एण्ड स्नोबोर्ड चैम्पियनशिप, ऋषिकेश में आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय योग महोत्सव, टिहरी लेक फैस्टिवल, जिम कॉर्बेट रामनगर में आयोजित होने वाले उत्तराखण्ड एडवेंचर सम्मिट तथा हिमालयन एमटीबी माउंटेन बाइकिंग आदि आगामी आयोजनों का वृहद रूप से प्रचार–प्रसार किया जा रहा है।

पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि इस प्रकार के आयोजनों में प्रतिभाग किये जाने से जहां एक ओर प्रदेशकी पर्यटन लोक संस्कृति, खान–पान एवं शिल्पकलाका व्यापक प्रचार–प्रसार होगा वहीं दूसरी ओर राज्य के निजी व्यवसाई लाभान्वित होंगे। साथ ही राज्य के साहसिक पर्यटन के गन्तव्य स्थलों का राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रचार–प्रसार होगा।